Jatre Mahotsav held here every 6 months along with various other festivals celebrated throughout the year, with a large number of devotees from across the Nation and abroad visiting the Temple.

Presently, the Temple area is rather small with many local shops and houses surrounding the Temple. The roads there are narrow and it is not possible to control the large number of pilgrims visiting that place. There is a lack of proper facilities and approach-roads for pilgrims. This historic and religious place needs improvement in all respects including widening of all roads leading to the Temple.

The Dattatreya Temple Committee under Chairmanship of the Deputy Commissioner, Kalburgi with assistance from the Central and State Governments, has prepared a master plan for the overall development of the Temple and for provision of various amenities for devotees visiting the Temple. The district administration has already made a request to the Union Ministry of Tourism to allocate rupees 83.52 crore under the PRASAD Scheme, to carry out the comprehensive development of the Temple.

Sir, the commitment of the Union Government for development of the spiritual and cultural sites as reflected in this Budget also, is commendable. Therefore, I urge upon the Government to consider the proposal submitted by the district administration under the PRASAD scheme at the earliest. With its rich culture and tradition, it is followed by lakhs of *people around the world as Guru Sathnam and it is considered as Dakshin Kashi*. There is a Jatre Mahotsav held every six months along with other major festivals celebrated round the year, with a large number of devotees from across the Nation and abroad visiting the temple."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Dr. Sasmit Patra (Odisha) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Jaggesh.

Demand to increase the number of sleeper class coaches in trains originating from Jharkhand State

श्री आदित्य प्रसाद (झारखंड): आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा देश भर में कई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं और नई-नई ट्रेन्स की पटरियां भी तेजी से बिछाई जा रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है, जिससे लोगों की वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होने के कारण, लोग प्रतीक्षा सूची में ही रह जाते हैं और ट्रेन की यात्रा नहीं कर पाते हैं। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता

हूं। जब मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, जिले में रहता हूं, प्रदेश में रहता हूं, तो प्रत्येक दिन लोगों की बातें मेरे पास आती हैं और मैं देखता हूं कि पत्र लिखने के बावजूद भी, यात्रियों का ट्रेन में जाना कंफर्म नहीं हो पाता है। चूंकि यह सस्ती यात्रा है, सुलभ यात्रा है, आज के दिन में अच्छी यात्रा हो रही है, इसलिए गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग के अधिकांश लोग ट्रेन की यात्रा को पसंद करते हैं। परंतु, यात्रियों की जितनी संख्या बढ़ गई है, उतनी बोगियां नहीं मिल पा रही हैं और बोगियां नहीं मिलने के कारण, जितनी यात्रा लोगों को करनी चाहिए, वे नहीं कर पा रहे हैं और टिकट कन्फर्म नहीं हो पा रही हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्लीपर क्लास की बोगियां जोड़ने की कृपा की जाए, जिससे कि यात्री, गाँव के लोग उसमें सफलतापूर्वक, सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकें। महोदय, मेरा यही आग्रह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Aditya Prasad: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh) and Dr. John Brittas (Kerala).

Provision of housing facilities to athletes

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): सर, सबसे पहले तो मैं उन 117 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो अभी पेरिस जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि वे बहुत अधिक संख्या में मेडल जीतकर वापस आएंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस साल खेल मंत्रालय को 3,442 करोड़ रुपये का बजट दिया है और हमारी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, स्पोर्ट्स को एक सब्जैक्ट का दर्जा दिया है। मणिपुर में इसके लिए देश के पहले राष्ट्रीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। महोदय, मैं सदन के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो हमारे खिलाड़ियों से संबंधित है। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण और जमीनी स्तर पर स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम पूरी शिद्दत से कर रही है और इन योजनाओं की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभाशाली युवा देश का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। इस योजना के तहत, 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 1,059 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना दी जा रही है। आज पूरे देश में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड हर जिले में बनाए जा रहे हैं तथा हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने पेरिस में आगामी ग्रामीण खेलो के लिए भारत की तैयारी पर 16 खेल विदाओं पर 470 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। हमारे खिलाड़ियों के पास खेल संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी असुविधा का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, वह आवास की है। आज ग्रामीण और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उन्हें शहर आना पड़ता है और वे या